भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2849
उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025

बीएसएनएल में संविदा कर्मचारी

2849. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीएसएनएल द्वारा 4जी और 5जी आरंभ करने में अत्यधिक देरी हुई है, जिसका मुख्य कारण स्वदेशी उपकरणों की ओर रुझान और उनके विकास एवं तैनाती से संबंधित चुनौतियाँ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) बीएसएनएल में संविदा कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनकी सेवा में शामिल होने की तिथि क्या है;
(ग) क्या इन कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की कोई योजना है;
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या बीएसएनएल के कर्मचारी केंद्रीय वेतन आयोग के स्थान पर औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अधीन होते हैं और यदि हाँ, तो क्या उन्हें केंद्रीय वेतन आयोग प्रारूप के अंतर्गत वापस लाने की कोई योजना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या बीएसएनएल में लगभग 30,000 गैर-कार्यकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से लगभग 12,000 कर्मचारी नौकरी के समान पद पर बने रहने की समस्या का सामना कर रहे हैं और परिणामस्वरूप उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है और क्या उनके लिए कोई पदोन्नति नीति कार्यान्वित करने की कोई योजना है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) आत्मनिर्भर भारत पहल की तर्ज पर बीएसएनएल ने अखिल भारतीय स्तर पर संस्थापना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइटों के लिए क्रय आदेश दे दिया है। 4जी उपकरणों की आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो गई है और दिनांक 30.06.2025 तक, कुल 95,537 4जी साइटें संस्थापित

की गई हैं, और 90,035 साइटें ऑन-एयर हैं। यह उपकरण प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से 5जी में अपग्रेड करने योग्य है।

(ख) से (घ) बीएसएनएल सीधे तौर पर संविदा कर्मचारियों को नियुक्त नहीं करता है। सभी गैर-मुख्य कार्यकलाप जैसे मरम्मत और रखरखाव, हाउसकीपिंग, सुरक्षा आदि सेवा स्तर करार/सेवा मॉडल पर हैं।

(ङ) बीएसएनएल कर्मचारी औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न के अधीन होते हैं और उन्हें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) प्रारूप के अंतर्गत लाने की कोई योजना नहीं है।

(च) और (छ) गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में स्थिरता बीएसएनएल की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वेतनमानों में संशोधन न होने के कारण है, क्योंकि बीएसएनएल लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित वहनीयता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

*****